

किसानों की समृद्धि में सहायक होगा पहला सहकारिता विश्वविद्यालय

किसानों की समृद्धि में सहायक होगा पहला सहकारिता विश्वविद्यालय

अरविंद दर्मा • जकारण

नई दिल्ली : किसानों की समृद्धि केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ही आश्रित नहीं है, बल्कि सहकारिता के माध्यम से भी इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे तेजी से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस विश्वविद्यालय का कैम्पस गुजरात के आणंद स्थित इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट (इरमा) में होगा, जोकि वर्तमान में एक सोसाइटी के

- यह पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई, इसी सत्र से पढ़ाई शुरू करने का प्रयास
- गुजरात के आणंद में बनेगा सहकारिता विश्वविद्यालय, डिग्री प्रोग्राम, दूरस्थ शिक्षा एवं ई-लर्निंग पाठ्यक्रम संचालित होंगे
- सहकारी क्षेत्र के लिए दक्ष पेशेवर होंगे तैयार, तकनीकी शिक्षा, लेखा और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण मिल सकेगा



रूप में पंजीकृत है।

इस विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दस पटेल के नाम पर रखा जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे और देश में सहकारी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। केंद्र सरकार

ने मौजूदा बजट सत्र में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के गठन के लिए विधेयक पेश किया है, जिसे संसद से जल्द ही पारित करने की योजना है। सरकार का प्रयास है कि इस शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाए।

विधेयक में कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारत में सहकारिता क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से व्यवस्थित करना है। वर्तमान में यह क्षेत्र बिखरा हुआ है और सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण असंगठित है। विभिन्न राज्यों और संस्थानों में अलग-अलग तरीके से कुछ कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें एकरूपता का अभाव है। देश में कृषि, उर्वरक वितरण, चीनी एवं दूध उत्पादन-खरीद, खाद्यान्न की खरीद एवं मछली उत्पादन आदि क्षेत्रों में सहकारी समितियां सक्रिय हैं, लेकिन इनमें कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम-शक्ति की कमी है। सहकारी क्षेत्र के विकास की गति को देखते हुए भविष्य में बड़ी संख्या में योग्य कर्मचारियों की

आवश्यकता होगी। विश्वविद्यालय का उद्देश्य सहकारिता में श्रेष्ठता के वैश्विक मानकों को प्राप्त करना है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह कार्य करेगा और इसमें डिग्री स्तर से पढ़ाई शुरू होगी। दूरस्थ शिक्षा एवं ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे, जिनमें सहकारिता क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार किए जाएंगे। विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा, लेखा एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण मिलेगा। विश्वविद्यालय की ओर से देश-विदेश में कहीं भी कैम्पस खोला जा सकता है। राज्यों के किसी न किसी विश्वविद्यालय में सहकारिता से संबद्ध पढ़ाई होगी, जिसकी संबद्धता सहकारिता विश्वविद्यालय के पास होगी। सहकारी कालेज भी खोले जा सकते हैं।
